SHRI T. G. VENKATESH: I would like to know from the Government whether they are working out a plan, like GST, on the power policy so that there would be a uniform power rate all over the country. Then, the survival of industry will be possible. Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, power squarely comes within the 'State Subjects' and, therefore, the Central Government at this moment has no plan in order to shift the responsibility from the States to the Centre. There is no such proposal, at all. But, if you recollect, the problem that the hon. Member has raised is the problem which was plaguing several electricity distribution companies in the States. One of the primary reasons was not being able to charge every consumer the cost of power, and the cross-subsidisation had made it costlier for a number of them. Many of the State discoms, therefore, were a part of this large NPA of the public sector banks. In fact, when we speak in terms of the NPAs, we speak of the infrastructure sector or the textiles sector or the steel sector; but, in the power sector, the State discoms are also a major contributor because of these reasons. The Central Government had come out with the UDAY scheme by which the State Governments were asked to take over the liabilities of the Boards so that the Boards could start operating on a larger commercial consideration in future.

MR. CHAIRMAN: Question No.409, please.

बैंकिंग प्रणाली पर विमुद्रीकरण के प्रभाव

*409. **श्री संजय राउतः** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विमुद्रीकरण के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंकों की साख वृद्धि में अत्यधिक गिरावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों पर विमुद्रीकरण का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है और सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि बैंकिंग प्रणाली को सुचारू बनाये जाने के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि यह पूंजी बैंकों को उपलब्ध कराई जाए, क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ऋण वृद्धि वैश्वक आर्थिक दृष्टिकोण, पण्य चक्र, वैश्विक बाजार में स्थायित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य वृहत्त आर्थिक घटकों पर निर्भर है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर, 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की सकल बकाया अग्रिम में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने विनियामकीय पूंजी मानदण्डों का पालन करते हुए तथा बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूंजीगत सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के कार्य को पूरा किया है। अगस्त, 2015 में आरंभ की गई 'इन्द्रधनुष' योजना के भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2019 तक 1,80,000 करोड़ रुपए की पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान लगाया गया कि इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपए पीएसबी द्वारा बाजार से जुटाए जाएंगे और 70,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा बजटीय आबंटन से निवेश किया जाएगा। अभी तक सरकार ने पीएसबी में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

सरकार समय-समय पर पीएसबी को उनकी पूंजी आवश्यकता, उनके शेयरों के कार्यनिष्पादन, चल निधि, बाजार की दशा जैसे मानदण्डों के आधार पर अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) अथवा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए सरकार की हिस्सेदारी 52% तक कम करने की अनुमति देती है।

Effects of demonetisation on banking system

†*409. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the credit growth of Public Sector Banks and private banks has witnessed a huge decline because of demonetisation;

(b) if so, the ill-effects of demonetisation on banks and the steps being taken by Government to correct the same;

(c) whether it is a fact that ₹1.80 lakh crore are required to streamline the banking system; and

(d) if so, the steps Government proposes to take to ensure that this capital is provided to the banks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Credit growth is dependent on factors such as global economic outlook, commodity cycle, stability in global markets, international trade and other macro-economic factors. As per data received from Reserve Bank of India, Gross outstanding advances for Public Sector Banks (PSBs) and Private Banks increased by over ₹ 80,000 crore between October 2016 and December 2016.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) and (d) The Government has carried out the exercise of capitalization of Public Sector Banks (PSBs) to conform to regulatory capital norms as well as to support capital demands of a growing economy. As part of "Indradhanush Plan" undertaken in August 2015, total capital requirement up to FY19 was estimated at ₹ 1, 80,000 crore. Out of this, it was estimated that ₹ 1,10,000 crore shall be raised by PSBs from the market while ₹ 70,000 crore shall be infused by the Government from budgetary allocation. So far, the Government has infused around ₹ 50,000 crore into PSBs.

From time to time, the Government permits PSBs to raise capital from public markets through Follow-on Public Offer (FPO) or Qualified Institutional Placement (QIP) by diluting Government of India holding upto 52% based on parameters like their capital requirement, their stock performance, liquidity, market conditions.

श्री संजय राउतः सभापति महोदय, मुझे क्वेश्चन नम्बर 408 में थोड़ा इसका उत्तर मिला है, लेकिन यह जो मेरा प्रश्न है, वह demonetisation के बारे में है। सरकार का मानना है कि नोटबंदी यानि demonetisation is a game changer. सरकार के लिए यह बात कहना आसान है, लेकिन ground reality ऐसी नहीं है। वर्ष 1954-55 के बाद first time बैंकों को लेकर देश चिंतित है, सरकार भी चिंतित होगी और credit growth में नोटबंदी के दौरान लगभग 6,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एस.बी.आई. ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बारे में चिंता व्यक्त की है। बैंकों से ऋण लेने वाले 10 ग्राहकों में से 7 ग्राहक गायब हैं और इस पर वे कहते हैं कि जब तक credit growth डबल डिजिट में नहीं आती है, तब तक बैंकों का बुरा हाल रहेगा। स्मॉल सेविंग्स करने वालों के बुरे दिन आए हैं, employment generate नहीं हो रहा है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बारे में भी reduction की बात, मैं देख रहा हूं।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस credit growth का सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है, उसको सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और नोटबंदी की इस ill-effect side में सुधार के लिए भी सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री संतोष कुमार गंगवारः माननीय सभापति जी, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, सामान्यतः ऐसी आशंका देश के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा मजबूत कदम है, जिसके परिणाम आने वाले समय में धीरे-धीरे समझ में आएंगे। महोदय, आंकड़े बताते हैं कि credit growth में वृद्धि हुई है और अगर हम दो महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि हम कहीं भी minus में नहीं गए हैं। महोदय, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस के सकारात्मक परिणाम नज़र आएंगे और आप को लगेगा कि इस महत्वपूर्ण कदम से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और हम इस संबंध में सही ढंग से आगे बढ़ेंगे।

श्री संजय राउतः सर, मैं इस संबंध में सरकार की भूमिका का समर्थन करता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन demonetisation के दौरान बैंकों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जमा हुए और वहीं तीन महीनों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की नई

करेंसी बाजार में आयी है। हमें नोटबंदी के दौरान उम्मीद थी कि अगले कुछ महीनों में interest rate में कटौती होगी और नौकरीपेशा लोगों को आसान रेट पर लोन मिलना संभव होगा, लेकिन credit growth में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। बैंकों में पैसा बेकार पड़ा है और लोन की demand लगाकार कम हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नोटबंदी से saving bank accounts में अचानक फंड बढ़ने और credit demand के कम होने से बैंकों को कितना नुकसान हुआ है? मेरे पास जानकारी है कि बहुत से बैंक अपने non-core assets बेचकर काम चला रहे हैं और छोटे-छोटे बैंकों की ब्रांचेज़ बंद की जा रही हैं, वहीं उन के स्टाफ में कटौती भी हो रही है। इसलिए मैं आप से जानना चाहूंगा कि क्या इसका सीधा असर बैंकों पर हो रहा है और आप उस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार: मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है और जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री जी ने 'इंद्रधनुष' योजना के बारे में बताया है, उस के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015 से 2019 के लिए हम ने अंदाजा लगाया था कि 1 लाख 80 हजार करोड़ के capital की आवश्यकता होगी। उसमें 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए मार्केट से, 70 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार अपने बजट से देगी। महोदय, इस बारे में हमें सकारात्मक उत्तर मिल रहे हैं। आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वह निर्मूल साबित होगी। महोदय, अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक response नज़र आ रहा है। हम लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है कि लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे थे, अब उस से आगे बढ़कर हम काम कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि आप को इसमें positive सुधार भी नज़र आएगा और आप को महसूस होगा कि वास्तव में demonetisation के बाद देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में, सही ढंग से चल रही है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister while delivering the Budget Speech had categorically stated that the liquidity in the banking system on account of post-demonetisation would result in lowering the borrowing cost, that is, lending rate and also improve the credit growth in the industry. Sir, according to Reserve Bank of India Monetary Policy Report, which has been released on 6th April, 2017, the credit growth remained sluggish at six per cent. So, I would like to know from the hon. Finance Minister whether the Ministry is taking any steps to improve the credit growth, which is sluggish and remained at six per cent on account of asset quality concerns. Thank you.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the hon. Member would realize that all steps which are taken to give boost to the economy are in that direction so that the economy grows. It also means that credit growth should increase. Alternative source of credit such as bonds, etc., have seen a significant revival. He may also remember, notwithstanding the monetary policy decisions of the Reserve Bank of India, immediately after the demonetisation in the first go itself, in the month of January, the Banks had cut their rates down by almost about 80 to 85 basis points, depending on different Banks. Recently, again, at the beginning of this month, I saw there was a

marginal cut by some banks. And, therefore, banks have themselves also been indulging in the exercise of cutting down the rates, essentially, because excess liquidity is available with banks and they want to use this amount.

SHRI D. RAJA: Sir, my supplementary is relating to the reply given to parts (c) and (d) of the main question. Arunji has already dealt that point. Even then, I wanted to put this supplementary.

The reply says, "As a part of 'Indradhanush Plan' undertaken in August 2015, total capital requirement up to FY 19 was estimated at ₹ 1,80,000 - crores. Out of this, it was estimated that ₹ 1,10,000 crores shall be raised by PSBs from the market while ₹ 70,000 crores shall be infused by the Government..." This is the reply given. It is a good positive step taken by the Government to infuse capital into public sector banks. But, why is there increase in the NPAs? The hon. Finance Minister is well aware that the primary reason for NPAs is the wilful default by corporate houses. And, Sir, wilful default is a crime. So, what action the Government is contemplating against wilful defaulters? Sir, at least, you should tell the names of defaulters to Parliament. In the name of secrecy, if you don't reveal the names, it is not fair. Parliament should know the names. So, I wanted to know what action the Government is initiating against the wilful defaulters.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, every NPA is not due to wilful default. There are separate categories. Under one category of NPA, a person is not able to service his loan for a period of ninety days, and, therefore, the performing asset becomes a Non-Performing Asset. A wilful default comes under a separate category altogether where one diverts money, does fraudulent exercises for which he is liable for criminal action, in addition to various actions. That is a separate category under the RBI guidelines. And, there is no provision which provides for any secrecy with regard to names of wilful defaulters. And, therefore, not only their names but also their photographs are printed.

SHRI D. RAJA: What action is the Government taking?

SHRI ARUN JAITLEY: In all cases of wilful default, not only are the recovery proceedings launched but even the criminal proceedings are launched.

SHRI ANIL DESAI: Sir, my supplementary question is not directly relating to the effects of demonetisation on banking system, but it is concerning the operative lines taken by private banks *vis-a-vis* public sector banks. If the hon. Finance Minister permits, I will ask my supplementary.

MR. CHAIRMAN: You don't need any permission. You just ask your question.

SHRI ANIL DESAI Sir, it is not directly on the effect of demonetisation.

Sir, public sector banks, apart from their core banking business, are also catering to industries and they also have to involve in various rural sector schemes of the Government where there are responsibilities and no profit is involved. Therefore, their percentage of profit always goes down as far as their core banking activity is concerned. But, private sector banks limit their activities in urban areas where you have cream of business. And, in the absence of a level-playing field, private sector banks are always going ahead of public sector banks and public sector banks are always under pressure. So, I would like to know whether the Government is thinking to rein in private sector banks' profits and whether any level-playing field mechanism proposed to be evolved and enforced accordingly.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, provisions regarding priority sector lending, etc., would be applicable to them. The hon. Member is right and that is how the market economy itself functions. Now, you have various kinds of banking activities which have expanded beyond private sector banks. You have a new category of Payment Banks coming up. You have banks which exclusively deal in digital transactions catering to a section of consumers. So, their activities will be of different kinds. At the moment, there is no proposal to regulate the activities. We have to allow these banking activities to expand. And, I am sure, the private sector banks will eventually play an important role in the industrial and the infrastructure development of the country, considering their size and their profitability.

Discrimination against civilian wards in Army schools

*410. SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Army Welfare Education Society (AWES), Delhi Area Headquarter has been violating the rules regarding refusal / delay in replying to letters from Members of Parliament / VIP References in matters relating to admission of civilian wards in Army schools, if so, the details thereof;

(b) whether AWES discriminates against civilian wards as compared to Defence wards in Army school which includes higher fees and lack of school bus facility to civilian wards;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government in this regard?